



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 19, 2012/आश्विन 27, 1934

No. 232]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 19, 2012/ASVINA 27, 1934

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2012

केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस (संशोधन)

विनियम, 2012

(2012 का 21)

फा. सं. 416-3/2010-आईएण्डएफएन.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

- 1 (1) इन विनियमों को केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस (संशोधन) विनियम, 2012 कहा जाएगा।
(2) ये विनियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2 केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007 (2007 का 5) (इसमें आगे इसे मूल विनियमों से निर्दिष्ट किया गया है) के विनियम 10 के उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए

जाएंगे अर्थात्:-

“(4) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट एक्सेस सरलीकरण प्रभार वैसे ही होंगे जैसे कि विनियम 3 के उप-विनियम (4) के तहत प्रकाशित केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में शामिल किए गए थे :

परन्तु यह कि प्राधिकरण को एक्सेस सरलीकरण प्रभारों में बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा, जो पात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी की श्रेणी या श्रेणियों द्वारा देय होंगे और ऐसे मामले में, इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा अनुसूची के भाग-II में यथा विनिर्दिष्ट एक्सेस सरलीकरण प्रभारों के लिए स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं होगी।

3 उप-विनियम (2) के लिए मूल विनियमों के विनियम 12 में निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित रद्दकरण प्रभार वैसे ही होंगे, जैसे कि विनियम 3 के उप-विनियम (4) के तहत प्रकाशित केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव में शामिल किए गए थे :

परन्तु यह कि प्राधिकरण को रद्दकरण प्रभारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा, जो पात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी की श्रेणी या श्रेणियों द्वारा देय होंगे और ऐसे मामले में, इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा अनुसूची के भाग-II में यथा विनिर्दिष्ट रद्दकरण प्रभारों के लिए स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं होगी।”

4 मूल विनियमों के विनियम 14 में उप-विनियम (2) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित जाएंगे, अर्थात्:-

“(3) उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित पुनःबहाली प्रभार वैसे ही होंगे जिन पर पात्र अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी और केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामियों के बीच सहमति थी या जो अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट किए गए थे:

परन्तु यह कि प्राधिकरण को पुनःबहाली प्रभारों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा जो पात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी की श्रेणी या श्रेणियों

द्वारा देय होंगे और ऐसे मामले में, इन विनियमों के तहत प्राधिकरण द्वारा अनुसूची के भाग-II में यथा विनिर्दिष्ट पुनःबहाली प्रभारों के लिए स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं होगी।”

- 5 मूल विनियमों के विनियम 16 में, उप-विनियम (2) के परंतुक में “परंतु यह कि प्राधिकरण इस अधिनियम के तहत बनाए गए अन्य विनियम द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है” शब्दों को “परंतु यह कि प्राधिकरण विनिर्दिष्ट कर सकता है” शब्दों से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

राजीव अग्रवाल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधारण/142/12]

टिप्पणी 1:— मुख्य विनियम, दिनांक 7 जून, 2007 (2007 का 5) की अधिसूचना के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे।

**केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय
दूरसंचार एक्सेस(संशोधन) विनियम, 2012
के लिए व्याख्यात्मक ज्ञापन**

क. प्रस्तावना

1. भादूविप्रा ने दिनांक 07.06.2007 को ‘केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं हेतु अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस विनियम, 2007’ जारी किए थे। इस विनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केबल लैंडिंग स्टेशन का स्वामी (ओसीएलएस) किसी पात्र भारतीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी (आईटीई) को निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण नियमों और शर्तों पर अपने केबल लैंडिंग स्टेशन में एक्सेस मुहैया कराएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि ओसीएलएस को अपने केबल लैंडिंग स्टेशनों में समुद्री केबल के लिए लैंडिंग सुविधाओं सहित एक्सेस सुविधाओं और सह-स्थान सुविधाओं की शर्तों एवं नियमों का उल्लेख करते हुए निर्धारित फॉर्मेट में “केबल लैंडिंग स्टेशन संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (सीएलएस आरआईओ)” भादूविप्रा को इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होगा। भादूविप्रा की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, ओसीएलएस को आरआईओ प्रकाशित करना होगा। तदनुसार, 2007 में, प्राधिकरण की स्वीकृति के बाद, केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों ने एक्सेस सरलीकरण प्रभारों और सह-स्थान प्रभारों का उल्लेख करते हुए एक आरआईओ प्रकाशित किया था। विनियम में यह भी प्रावधान है कि इन विनियमों के लागू होने के बाद, अस्तित्व में आने वाले केबल लैंडिंग स्टेशन के मामले में, ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को ऐसे केबल लैंडिंग स्टेशन के अस्तित्व में आने की तारीख

को या उससे पहले उक्त केबल लैंडिंग स्टेशन के संबंध में केबल लैंडिंग स्टेशन-संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव भादूविप्रा को इसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना होगा।

2. वर्ष 2010 में, कुछ सेवा प्रदाताओं ने भादूविप्रा को यह अभ्यावेदन दिया था कि केबल लैंडिंग स्टेशन पर एक्सेस सरलीकरण प्रभार और सह-स्थान प्रभारों की समीक्षा करने की आवश्यकता है क्योंकि पिछले तीन वर्षों में दूरसंचार उपकरणों के मूल्यों में तो कमी आई है मगर केबल लैंडिंग स्टेशनों के क्षमता उपयोग में बढ़ोतरी हुई है।
3. एक्सेस सरलीकरण प्रभारों, वार्षिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) प्रभारों और सह-स्थान प्रभारों को वर्तमान लागतों और उपयोग के अनुरूप बनाने के मद्देनजर, भादूविप्रा ने दिनांक 06.10.2010 के पत्र द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशनों (ओसीएलएस) के स्वामियों को अपने केबल लैंडिंग स्टेशनों (सीएलएस) के लिए संशोधित एक्सेस सरलीकरण प्रभार, वार्षिक प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओएंडएम) प्रभार और सह-स्थान प्रभार पुनः प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके जवाब में, ओसीएलएस ने अपने विभिन्न केबल लैंडिंग स्टेशनों के लिए एक्सेस सरलीकरण प्रभार और सह-स्थान प्रभार प्रस्तुत किए थे। कुछ नए केबल लैंडिंग स्टेशन, जो कि बाद में अस्तित्व में आ गए थे, के स्वामियों ने भी अपने केबल लैंडिंग स्टेशनों के लिए आरआईओ प्रस्तुत किए गए।
4. इस बीच, भादूविप्रा को कुछ सेवा प्रदाताओं और उनकी एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, जिसमें उन्होंने एक्सेस सरलीकरण प्रभारों की समीक्षा पर उद्योग की सभी कंपनियों के साथ औपचारिक रूप से गहन विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया था। उन्होंने उल्लेख किया कि 2007 से आईपीसीएल के मूल्यों में भारी कमी के साथ-साथ समुद्री केबल प्रणालियों की क्षमता उपयोग में घातांकीय वृद्धि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ मार्केट में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में प्रमुख केबल लैंडिंग स्टेशनों में अंतर्राष्ट्रीय क्षमता उपयोग में 2007 के बाद से कम से कम 10 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने यह तर्क दिया कि क्षमता उपयोग में हुई वृद्धि के समानुपात में सरलीकरण प्रभारों और प्रचालन एवं अनुरक्षण(ओएंडएम) प्रभारों में कमी की जानी चाहिए। सेवा प्रदाताओं का यह भी कहना था कि इन प्रभारों में, 2007 के बाद से कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, सीएलएस सुविधा लगातार एक अवरोधक सुविधा बनी हुई है और इसलिए आईएलडीओ, जिसके अपने केबल लैंडिंग स्टेशन नहीं हैं, के क्षेत्र में कोई प्रभावी प्रतिस्पर्धा संभव नहीं हो पाई है। उन्होंने यह भी अभ्यावेदन दिया :—

- (1) भारत में सीएलएस एक्सेस प्रभार बहुत ही अधिक हैं तथा अन्य दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों से तुलना करने से ज्ञात होता है कि इन देशों में लागू प्रभार भारत में प्रभारित किए जा रहे प्रभारों के नाममात्र के बराबर है।
- (2) दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दूरस्थ पूर्व और पश्चिमी यूरोप क्षेत्र में केबल लैंडिंग स्टेशन सुविधाओं तक एक्सेस के लिए विभिन्न (मल्टीपल) प्रभार नहीं हैं बल्कि नाममात्र का आरआईओ/ क्रास-कनेक्ट प्रभार लिया जाता है क्योंकि अधिकांश प्रचालन और आवर्ती लागतें, एसोसिएशन के सदस्यों और मूल हस्ताक्षरकर्ताओं से वसूली जाती हैं।
- (3) एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य द्वारा सीएलएस स्वामी के रूप में, इन स्टेशनों को चलाने से संबंधित लागत अर्थात् भवन एवं प्रचालन व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

5. इस मामले में, भिन्न विचारों का समाधान करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भादूविप्रा ने इस मुद्दे पर एक परामर्श प्रक्रिया शुरू की। दिनांक 22.06.2011 को आईएलडी सेवा प्रदाताओं और उनकी उद्योग एसोसिएशनों को एक पत्र भेजा गया था, जिसमें उन्हें लागत डाटा तथा 'केबल लैंडिंग स्टेशनों में अनिवार्य सुविधाओं तक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार एक्सेस' से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

6. सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जवाबों का विश्लेषण करने के उपरांत, भादूविप्रा ने दिनांक 22.03.2012 को 'केबल लैंडिंग स्टेशनों पर एक्सेस सरलीकरण प्रभारों और सह-स्थान प्रभारों' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीखें क्रमशः 05.04.2012 और 12.04.2012 रखी गई थी। बाद में, ये तारीखें बढ़ाकर क्रमशः 19.04.2012 और 26.04.2012 कर दी गई थी।

ख. प्राप्त जवाबों और ओसीएलएस द्वारा प्रस्तुत लागत डाटा का विश्लेषण

7. परामर्श पत्र के जवाब में, 24 और 8 हितधारकों ने क्रमशः टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां भेजी थी। ज्यादातर हितधारकों की यह राय थी कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मार्केट में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एक्सेस सरलीकरण प्रभारों

और सह-स्थान प्रभारों में कमी करके, इन्हें उचित और तुलनात्मक स्तर पर लाने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके अलावा, हितधारकों का सामान्यतः यह मानना था कि केबल लैंडिंग स्टेशनों (ओसीएलएस) के स्वामियों द्वारा जांच करने के उपरांत ही एक्सेस सरलीकरण प्रभार और सह-स्थान प्रभार, भादूविप्रा को प्रस्तुत किए जाएं तथा ओसीएलएस से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगने के उपरांत ही इन प्रभारों को निर्धारित करने के तौर-तरीकों सहित प्रभारों को प्रकाशित करना चाहिए। एक हितधारक ने यह भी उल्लेख किया कि भादूविप्रा द्वारा एएफसी और सीएलसी तय करने की विधि, मौजूदा परिदृश्य में ज्यादा उपयुक्त है, जिसमें इन प्रभारों को अधिक शक्तिशाली और सतत विनियमों की जरूरत है, जब तक कि प्रतिस्पर्धा, इन प्रभारों को संभाले और एएफसी और सीएलसी सहित बैंडविड्थ मूल्य अपने आपको अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप बना लेते हैं।

8. अन्य हितधारकों का यह भी मत था कि प्रचलित व्यवस्था अर्थात् केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा एएफसी और सीएलसी प्रस्तुत करने और भादूविप्रा द्वारा जांच के बाद स्वीकृति देने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। पिछले चार वर्षों में, बैंडविड्थ प्रभारों में महत्वपूर्ण कमी आई है जबकि एएफसी और सीएलसी में कोई बदलाव नहीं आया है। इस समय, ये प्रभार, बैंडविड्थ की कुल लागत के 56 प्रतिशत से भी अधिक हैं, जो काफी अधिक है और यदि इन्हें नीचे नहीं लाया गया तो यह अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ मार्केट में प्रतिस्पर्धा को अवरुद्ध कर देगी। हितधारक ने यह भी सुझाव दिया कि भादूविप्रा द्वारा लागत आधारित एएफसी और सीएलसी निर्धारित करने की विधि, ऐसी स्थिति में ज्यादा उपयुक्त नहीं है, जहां बीडब्ल्यू प्रभारों के प्रतिशत के रूप में ये प्रभार काफी अधिक हैं। एक एसोसिएशन ने यह भी टिप्पणी की कि दक्षिण पूर्व एशिया के देश, दूरस्थ पूर्व और पश्चिमी यूरोप क्षेत्र में केबल लैंडिंग स्टेशन सुविधाओं तक एक्सेस के लिए विभिन्न (मल्टीपल) प्रभार नहीं हैं बल्कि नाममात्र का आरआईओ/क्रास-कनेक्ट प्रभार लिया जाता है क्योंकि अधिकांश प्रचालन और आवर्ती लागतें, एसोसिएशन के सदस्यों और मूल हस्ताक्षरकर्ताओं से वसूली जाती हैं। एक और हितधारक ने बताया है कि भादूविप्रा को लागत आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू करनी चाहिए और उसने यह भी उल्लेख किया कि परामर्श पत्र में दिए गए अन्य विकल्प दी गई परिस्थितियों और आज तक के अनुभव को देखते हुए बेहद अनुचित हैं।

9. केबल लैंडिंग स्टेशनों के स्वामियों, जो कि अधिकांश केबल लैंडिंग स्टेशनों के मालिक थे, ने यह उल्लेख किया कि सीएलएस को एक आवश्यक/अवरोधक सुविधा के रूप में मानना, जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है और मौजूदा एएफसी और सीएलसी को बाजार शक्तियों के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए।
10. प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि भारत में समुद्री केबल लैंडिंग प्रणालियों की संख्या 2007 में 10 थी, जो अब बढ़कर 15 हो गई है। इसमें आगे और बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह भी उल्लेख किया गया है कि विभिन्न केबल प्रणालियों के लिए मौजूदा 15 केबल लैंडिंग स्टेशनों में से विभिन्न केबल प्रणालियों के लिए 12 केबल लैंडिंग स्टेशन, दो ओसीएसएल के स्वामित्वाधीन हैं। विनियम के मौजूदा प्रावधान के अनुसार, केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा केबल लैंडिंग स्टेशन के अस्तित्व में आने से पहले, भाग-II में उल्लिखित प्रभारों सहित सीएलएस-आरआईओ प्रस्तुत करना जरूरी है। केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी द्वारा प्रस्तुत प्रभारों पर, उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकता होती है और ओसीएसएल से पूरा विवरण प्राप्त होने के बाद, प्राधिकरण द्वारा इन प्रभारों को 60 दिनों के अंदर स्वीकृति देनी जरूरी होती है। चूंकि प्रभारों को स्वीकृति देने की प्रक्रिया में लागत निर्धारक घटकों का विवरण, लागतें और ओसीएसएल द्वारा अपनाई गई लागत निर्धारण पद्धति और भादूविप्रा द्वारा अंतिम स्वीकृति में ज्यादा समय लगता है और केबल लैंडिंग स्टेशन के स्वामी को प्रतिस्पर्धी फायदा मिलता है क्योंकि समुद्री केबल प्रणाली में ओसीएसएल भी एक एकीकृत ऑपरेटर स्वामित्वपूर्ण बैंडविड्थ होता है। प्राधिकरण ने आगे यह भी नोट किया है कि यद्यपि एक्सेस सरलीकरण मुहैया कराने में किया गया कार्य, विशिष्ट केबल लैंडिंग स्टेशन पर ध्यान दिए बिना, एक समान है जबकि विभिन्न ऑपरेटरों के बीच एक्सेस सरलीकरण एवं सह-स्थान प्रभार, उनके नेटवर्क विन्यास एवं लागत पद्धति के आधार पर अलग-अलग होता है।
11. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने विनिर्दिष्ट एक्सेस सरलीकरण प्रभार, सह-स्थान प्रभार और अन्य संबंधित प्रभारों जैसे कि रद्दकरण प्रभारों एवं पुनःबहाली प्रभारों के लिए उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए विनियमों में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2012

**International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable
Landing Stations (Amendment) Regulations, 2012**
(No. 21 of 2012)

F.No. 416-3/2010-I&FN.—In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (ii),(iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007 (5 of 2007), namely :-

1. (1) These regulations may be called the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations (Amendment) Regulations, 2012.
- (2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 10 of the International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007 (5 of 2007), (hereinafter referred to as the principal regulations), after sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
 - “(4) The Access Facilitation Charges referred to in sub-regulation (1) and sub-regulation (2) shall be such as had been included in the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer published under sub-regulation (4) of regulation 3 :

Provided that the Authority may specify Access Facilitation Charges which shall be payable by a class or classes of eligible Indian International Telecommunication Entity and in such case the approval of the Access Facilitation Charges, as specified in Part II of the Schedule, by the Authority shall not be required to be obtained under these regulations.

3. In regulation 12 of the principal regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(2) The cancellation charges referred to in sub-regulation (1) shall be such as had been included in the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer published under sub-regulation (4) of regulation 3 :

Provided that the Authority may specify cancellation charges which shall be payable by a class or classes of eligible Indian International Telecommunication Entity and in such case the approval of the cancellation charges, as specified in Part II of the Schedule, by the Authority shall not be required to be obtained under these regulations.”

4. In regulation 14 of the principal regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulations shall be inserted, namely:-

“(3) The restoration charges referred to in sub-regulation (1) and (2) shall be such as had been mutually agreed between the eligible International Telecommunication Entity and owner of Cable Landing Station or as specified in Part II of the schedule :

Provided that the Authority may specify restoration charges which shall be payable by a class or classes of eligible Indian International Telecommunication Entity and in such case the approval of the restoration charges, as specified in Part II of the Schedule, by the Authority shall not be required to be obtained under these regulations.”

5. In regulation 16 of the principal regulations, in proviso to sub-regulation (2), for the words “Provided that the Authority may specify, by other regulation made by it under the Act”, the words “Provided that the Authority may specify” shall be substituted.

RAJEEV AGRAWAL, Secy.

[ADVT.III/4/Exty./142/12]

Note 1:— The principal regulations were published vide notification dated 7th June 2007 (5 of 2007).

**Explanatory Memorandum to the ‘International
Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable
Landing Stations (Amendment) Regulations, 2012’**

A- Introduction

1. TRAI issued ‘International Telecommunication Access to Essential Facilities at Cable Landing Stations Regulations, 2007’ on 07.06.2007. The Regulations provides that the owner of cable landing station (OCLS) shall provide access to any eligible Indian International Telecommunication Entity (ITE) on fair and non-discriminatory terms and conditions, at its cable landing stations. It further provides that OCLS is required to submit a ‘Cable landing Station Reference Interconnect Offer (CLS RIO)’ to TRAI, in a specified format, containing the terms and conditions of access facilities and co-location facilities including landing facilities for sub-marine cables at its cable landing stations for its approval. After getting approval from TRAI, OCLSs are required to publish the RIO. Accordingly, in 2007, after approval of the Authority, owners of cable landing stations published their RIO containing access facilitation charges and co-location charges. The regulations also provides that in case of a cable landing station which comes into existence after commencement of these regulations, the owner of such cable landing station is required to submit, on or before the date of coming into existence of such cable landing station, the Cable Landing Station-Reference Interconnect Offer in respect of such cable landing station to the Authority for its approval.
2. In the year 2010, some of the service providers represented to TRAI that the access facilitation charges and co-location charges at cable landing station need a review as the cost of telecom equipment has gone down while the capacity utilization of cable landing station has gone up over the previous three years.

3. With a view to align Access Facilitation Charges, Annual O&M Charges and Co-location Charges with the current costs and utilization, TRAI vide its letter dated 06.10.2010 asked all the owners of cable landing stations (OCLSs) to resubmit the revised Access Facilitation Charges, Annual O&M Charges, Co-location Charges for all of their cable landing stations (CLSs). In response, the OCLSs submitted the Access Facilitation Charges and Co-location charges for their various cable landing stations. The owners of some of the new cable landing stations which came into existence subsequently also filed RIO for their new Cable Landing stations.
4. In the meantime, TRAI received representation from some of the service providers and their association requesting formal broad based consultation with all industry players on review of Access Facilitation Charges. They submitted that there has been a dramatic change in the international bandwidth market both in terms of a significant drop in the prices of IPLC as well as an exponential rise in capacity utilization of submarine cable systems since 2007. They further submitted that international capacity utilization at the major cable landing stations in India has gone up by at least 10 times since 2007. They have argued that the increased capacity utilization should have translated in proportional reduction in Access Facilitation Charges and Operation and Maintenance (O&M) Charges. The service providers further submitted that these charges have remained virtually unchanged since 2007, as a result, CLS facility continues to remain a bottleneck facility and, therefore, there is no effective competition possible in the sector for the ILDOs, who do not own cable landing stations. They also represented that:
 - i. CLS access charges in India are extremely high and a comparison with other South East Asian countries shows that the charges prevalent in these countries are just a fraction of what is being charged in India;
 - ii. Countries in South East Asia, Far East and Western Europe regions do not have multiple charges for access to

cable landing station facilities but levy a token RIO/cross-connect charge as most of the operational and recurring costs are recovered from consortium members and original signatories;

- iii. Each consortium reimburses CLS owners the cost associated with buildings and operational expenses in running these stations.

5. In order to address divergent views in the matter and to protect the interests of service providers and consumers of the telecom sector TRAI initiated consultation process on the issue. A letter dated 22.06.2011 was sent to the ILD service providers and their industry associations to furnish cost data and comments on various issues including international practices pertaining to 'International Telecommunication Access to Essential facilities at Cable Landing Stations'.
6. After analyzing responses received from service providers, TRAI issued consultation paper on 'Access Facilitation Charges and Collocation Charges at Cable Landing Stations' on 22.03.2012. Last date for comments and counter comments was 05.04.2012 and 12.04.2012 respectively. These dates were further extended to 19.04.2012 and 26.04.2012 respectively.

B- Analysis of Response received and the cost data submitted by the OCLSS

7. In response to the consultation paper comments and counter comments were sent by 24 and 8 stakeholders respectively. Majority of the stakeholders were of the view that there is an urgent need to reduce the Access Facilitation Charges and Co-location Charges to reasonable and comparable level in order to ensure continued growth in India's international telecommunication market. Further, the stakeholders were generally of the view that access facilitation charges and co-location charges submitted by the Owner of Cable Landing Stations (OCLS) to TRAI should, after scrutiny and seeking necessary

clarifications from the OCLS, be published along with the methodology used for arriving at the charges. One of the stakeholders submitted that the method of fixing of AFC and CLC by TRAI is more appropriate in the present situation where these charges need stronger and continuous regulation till such time the competition takes care of these charges and the bandwidth prices along with AFC and CLC aligned themselves with the international prices.

8. Another stakeholder was of the view that the prevalent arrangement i.e. submission of AFC and CLC by owner of the cable landing station and approval by the TRAI after scrutiny has not served the purpose. In the last four years, the bandwidth charges have come down significantly but AFC and CLC have remained the same. These charges are now as high as 56% of the total bandwidth cost which is quite significant and if not brought down, will stifle competition in the international bandwidth market. The stakeholder further suggested that the method of fixing cost based AFC and CLC by TRAI is the most appropriate in the given situation when these charges are significantly high as a percentage of the BW charges. One of the association submitted that countries in South East Asia, Far East and Western Europe regions do not have multiple charges for access to cable landing station facilities but levy a token RIO/ cross-connect charge as most of the operational and recurring costs are recovered from consortium members and original signatories. Another stakeholder also preferred that TRAI should impose cost based pricing and mentioned that other options given in the consultation paper are highly inappropriate given the circumstances and experience to date.
9. The owners of the Cable Landing stations who own majority of cable landing stations submitted that there is no justification to continue treating CLS as an essential/bottleneck facility and the existing AFC and CLC should be left to the market forces.

10. The Authority noted that the number of submarine cable systems landing in India have now increased to 15 from the earlier 10 nos. as in 2007 and these numbers are further likely to increase. Further, it has also been noted that out of present 15 nos. of Cable Landing stations for various cable systems, 12 nos. of Cable Landing Stations for various cable systems are owned by two OCLSs. As per the present provision of the regulation owner of cable landing station is required to submit the CLS-RIO including charges mentioned in Part-II of the schedule before the date of coming into existence cable landing station. The charges submitted by owner of the cable landing station are required to be further discussed with them and after getting complete details from the OCLS these charges are required to be approved by the Authority in 60 days. Since the process of approval of the charges involve scrutiny by TRAI of costing elements considered, costs and costing methodology employed by OCLS and final approval by TRAI, it takes more time and provides competitive advantage to the owner of cable landing station as OCLS is also integrated operator owning bandwidth in submarine cable system. The Authority further noted that though the work done in providing Access Facilitation is same irrespective of specific cable landing station, the Access Facilitation and Co-location charges varies between different operators based on their network configuration and costing methodology.
11. In view of the above, the Authority has decided to amend the regulations making suitable provisions for specifying Access Facilitation Charges, Co-location Charges and other related charges like Cancellation Charges and Restoration Charges.